

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास- श्री अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -194/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2023/228

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
दुडाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल, निवासी कालियास तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा, राज0

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री श्रवण बडियासर ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

निर्णय

दिनांक :-22.05.2024

अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 193/2022 सरकार बनाम दुडाराम में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने बहस में कथन किया पटवार हल्का माणकपुर ने अपीलांत के खिलाफ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार,मूण्डवा को प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कालियास के खसरा संख्या 106 गैर मुमकिन गोचर पर अपीलांत के द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही मौके पर से बेदखल करने व वार्षिक लगान का 50 गुणा कुल 04 रुपये बतौर शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान वकील अपीलांत का यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में आवेदनकर्ता पटवारी हल्का के द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगाया है कि उसके द्वारा खसरा संख्या 106 सरहद कालियास की भूमि पर संवत 2079 में नाजायज कब्जा कर लिया है, उक्त आरोप व आवेदन में वर्णित तथ्य पूर्णतया बेबुनियाद, काल्पनिक और मनगढन्त है। अप्रार्थी के द्वारा संवत 2079 में खसरा संख्या 106 की भूमि पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है और न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अप्रार्थी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो। अप्रार्थी का मौके पर उक्त मकान व बाड़ा वर्षों पहले से बना हुआ है,इसलिए संवत 2076 में मकान बनाने के तथ्य अपने आप में ही मिथ्या व असत्य साबित हो जाते हैं।

प्रार्थी के द्वारा खसरा संख्या 106 पर जिस प्रकार से अप्रार्थी का संवत 2079 में नाजायज अतिक्रमण करना बताया है वस्तुतः संवत 2079 में अप्रार्थी के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा संख्या 106 का पूरा भाग गोचर के रूप में कभी भी काम में नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ भूमि गैर मुमकिन आबादी की भूमि भी है। अपीलांत अपनी पुश्तैनी निर्मित मकान व बाड़ा की भूमि पर काबिज है। अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। इसके अलावा खसरा संख्या 106 की भूमि पर वर्षों से लोग परिवार सहित निवास कर रहे हैं। इन सब तथ्यों को छिपाते हुए गलत आरोप लगाकर यह आवेदन पेश किया गया है।



कलक्टर नागौर

विचारण न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही गलत प्रकार से की गयी थी और अपीलांट को प्रकरण में जबाब साक्ष्य सबूत के विधिक अवसर से वंचित किया गया है जबकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था अधीनस्थ न्यायालय ने इस स्थिति को नजर अंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट अपनी बढेरों के द्वारा बने हुए मकान व बाड़े की जायगा पर आबादी भूमि पर काबिज है तथा दो दूकाने भी बनी हुई है और उसका कोई अतिक्रमण नहीं है तथा मौके पर बिजली का कनेक्शन भी विधिवत रूप से ले रखा है।

खसरा संख्या 106 का पूरा भाग कभी भी गोचर भूमि के काम में नहीं आया है और मौके पर आबादी भूमि रही हैं। राजस्व रेकॉर्ड में गलत प्रकार से गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। स्वयं राज्य सरकार के द्वारा मौके पर आबादी भूमि होना मानकर काफी लोगों के इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृत किये गये हैं जो मौके पर मकान बने हुए है और लोगो का रहवास है तथा बिजली पानी के कनेक्शन भी लिये हुए है। इस प्रकार मौके पर वर्षों से रहना स्पष्ट प्रमाणित है तथा स्वयं सरकारी कार्यालयों के द्वारा मौके पर निवास व पक्के निर्माण होना मानकर ही बिजली पानी के कनेक्शन जारी हुए है और इन्दिरा आवास के तहत पक्के मकान बने हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी पर गलत आरोप लगाकर उक्त आवेदन पेश किया गया है।

खसरा संख्या 106 गोचर की भूमि अलग है और मौके पर गोचर भूमि के रूप में कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जिस पर अप्रार्थी ने कभी अतिक्रमण किया हो। गोचर भूमि मौके पर खाली पड़ी है। अप्रार्थी का निवास व मकान आबादी के चिपते स्थित भूमि पर है और अप्रार्थी का गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी के द्वारा बिना नाप चौप किये ओर राजस्व रेकॉर्ड तथा मोके की स्थिति को बिना कन्सीडर किये गलत तथ्यों पर यह आवेदन पेश किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा सरसरी तौर पर गलत तथ्यों के आधार पर यह आवेदन पेश किया है, जबकि मौके पर सरकारी भूमि व आबादी भूमि पर स्थित लोगो के रहवास व खसरा संख्या 106 की सही स्थिति की कोई रिपोर्ट उनके द्वारा पेश नहीं की गयी है।

अपीलांट गरीब काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है और उसके पास विवादित जायगा के अलावा अन्य कोई रहवास की जायगा नहीं है। यदि अप्रार्थी के सैंकड़ों सालों से चले आ रहे रहवास को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाकर बेदखल किया जाता है तो अप्रार्थी व उसके परिवार को बेघर होना पड़ेगा तथा अप्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। तहसीलदार जी द्वारा अपीलांट के अन्य कोई जमीन होने की रिपोर्ट इस प्रकरण में प्राप्त किये जाने पर भू0अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2023 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट के नाम ग्राम कालियास में कोई भूमि नहीं है।

अतः निवेदन है कि अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 193/2022 बअनबान सरकार बनाम दुडाराम में पारित आदेश जैर अपील दिनांक 26.09.2023 खारिज फरमाया जावें। अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो दिलाया जावें।

राजकीय परोकार का दौराने बहस कथन है कि ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 106 की किस्म गैर मुमकीन गोचर हैं। इस प्रकार की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित भूमियों की श्रेणी में आती हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 गोचर भूमि पर बिना किसी अधिकार के निर्माण कर मकान एवं बाड़ा बनाकर कब्जा किया है। तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो यह कार्यवाही की है, यह विधिवत् कार्यवाही है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि पटवारी हल्का माणकपुर द्वारा तहसीलदार को इस आशय की रिपोर्ट की पेश की है कि श्री दूडीराम पुत्र रूपाराम, जाति-मेघवाल,



कलक्टर नागौर

निवासी कालियास ने ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0161 हैक्टर किस्म जमीन गै0मु0गोचर पर सम्बत् 2079 से अनाधिकृत कब्जा द्वारा मकान कर रखा है। पटवारी पटवार मण्डल माणकपुर की इस रिपोर्ट के आधार पर पहले यह प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार, मूण्डवा में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बाद में दिनांक 13.06.2023 को यह प्रकरण न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा में प्रकरण संख्या 172/2023 दर्ज रजिस्टर किया गया। इस प्रकरण में गैर सायल दिनांक 30.01.2023 को न्यायालय नायब तहसीलदार, मूण्डवा में उपस्थित रहा तथा दिनांक 25.08.2023 को न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा में उपस्थित होकर उनका अतिक्रमण होना एवं मौके से स्वतः हटाने हेतु पर्याप्त समय चाहा गया प्रकट कर आदेशिका में स्वयं ने हस्ताक्षर भी किये हैं। जिससे वकील अपीलांट का यह कथन पूर्णतया अपने आप में गलत है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह प्रकट है कि अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये गये हैं।

पटवारी पटवार मण्डल, माणकपुर द्वारा पेश की गई गैर सायल के विरुद्ध नाजायज अतिक्रमण रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम कालियास के खसरा 106 रकबा 0.0161 है0 गै0मु0 गोचर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है। खसरा नम्बर 106 जो राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि है इस भूमि पर अपना स्वामित्व पूर्ण विधिक कब्जा होने के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किये हैं, जिससे तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी मानते हुवे जो निर्णय दिनांक 26.09.2023 को पारित किया है, जिसमें कोई विधि त्रुटि या फिर अवैधानिक कार्यवाही होना नहीं पाया जाता है। गै0मु0 गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है। इसलिए इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं न ही अधिकार दिये जा सकते हैं। अपीलांट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित होकर इस जमीन पर स्वयं का अतिक्रमण होना एवं अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय दिये जाने का निवेदन न्यायालय से किया है। इस प्रकार अपीलांट स्वयं ने अपना कब्जा अनाधिकृत माना है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार पुरोहित)
कलकत्ता नागौर

कलकत्ता नागौर